National Foundation for Communal Harmony has provided assistance to 1006 children so far. Assistance at the rate of Rs. 425/- per month per child in class 'A' and 'B' cities and at the rate of Rs. 375/- per month per child at other places is provided.

(b) The Foundation has so far provided assistance to 39 children from Andhra Pradesh, 8 children from Assam, 44 children from Bihar, 273 children from Gujarat, 66 children from Karnataka, 43 children from Rajasthan, 145 children from Madhya Pradesh, 255 children from Maharashtra, 117 children from Uttar Pradesh and 16 children from Delhi.

(c) The National Foundation for Communal Harmony has not so far received any proposal from the Government of Karnataka for providing assistance to the children of the victims of Urdu Telecast disturbances in Karnataka in October, 1994.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु पंजाब से प्राप्त प्रस्ताव

1701. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु पंजाब सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि की मांग की गई थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 1993-94 और 1995-96 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए पंजाब से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 430 लाख रुपये की कुल सहायता की मांग में से अब तक इस मंत्रालय द्वारा 2000 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

1702. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान् पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और उनकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 से अप्रैल, 1995 तक देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और उनकी मांग में प्रतिवर्ष किस दर से वृद्धि हुई,

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने के लिए देश में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग में लाए गये पेट्रोल, डीजल और गैस की मात्राओं का पता लगाया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) (क) और (ख) मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के वर्ष 1991 से 1995 तक के भंडारण स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क सहित) संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं **(नीचे देखिये)**

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 3.5%, 3.4%, 3.2% और 7.7% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और एल पी जी की खपत का अलग-अलग निर्धारण नहीं किया जाता।

विवरण

1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण-स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क सहित)

रुपए/विक्रय इकाई

	1991	1992	%वृद्धि	1993	%वृद्धि	1994	%वृद्धि	1995	%वृद्धि
एम एस-87	11180.09	13416.11	20.00%	14413.21	7.43%	15413.21	6.94%	15413.21	.00%
एचएसडी	4541.91	4541.91	.00%	5539.01	21.95%	6289.01	13.54%	6289.01	.00%
एसकेडी (घरेलू)	2446.16	2201.54	-10.00%	2201.54	.00%	2201.54	.00%	2201.54	.00%
एल पी जी (पैकड घरेलू)	3448.98	4130.78	20.00%	5135.88	24.09%	5840.11	13.71%	5840.11	.00%

Privatisation of Marketing of Petroleum Products

1703. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of State Governments have written to the Central Government against the decision of the latter to allow private companies to market kerosene and LPG without any restrictions; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) While the Ministry had received a message from the Government of West Bengal in February, 1993, protesting against the introduction of Parallel Marketing of Kerosene and LPG and expressing apprehensions of diversion of Kerosene under Public Distribution system (PDS) and subsidised LPG into the open market, and requested immediate reversal of the decision, the West Bengal Government has in April, 1994 issued orders and guidelines to its officials regarding the implementation of Parallel Marketing System in the state.

The Parallel Marketing System enables greater availability of kerosene and LPG in the free market. Necessary safeguards have been taken to prevent diversion of PDS kerosene and subsidised LPG into the Parallel Marketing Network. Parallel Marketing System is now working successfully in different States. Further to protect the interest of the consumers and to educate them about the capabilities and credibilities of the parallel marketeers, rating of parallel marketeers has been introduced from June, 1995, under which the Parallel marketeers have to obtain rating from a nominated agency and have to declare and publish the same in all communications.

दिल्ली में रेड-लाईन बसों द्वारा की गई दुर्घटनाएं

1704. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छहः महीनों के दौरान दिल्ली में रेड लाईन बसों द्वारा की गई दुर्घटनाओं के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी दुर्घनाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) 1.5.95 से 15.11.95 तक रेड लाइन बसें दिल्ली में 590 दुर्घनाओं के लिए जिम्मेदार थीं।

(ख) जी हां।

(ग) रेड लाइन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के